अधूरी योजनाओं के सहारे पहाड़िया कैसे चढ़ें विकास के पहाड़

जसिन्ता केरकेट्टा

क्यों चली जाती हैं क्षेत्र की सारी महिलाएं बंगाल ? जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर हिरणपुर प्रखंड में है श्यामपुर गांव। इस गांव की लगभग सारी महिलाएं हर साल बंगाल पलायन करती हैं। वहां वे खेतों में मजदूरी करती हैं। आजीविका का सबसे बड़ा साधन बंगाल जाकर मजदूरी करना ही है। मजदूरी तो मनरेगा भी देता है फिर वे मनरेगा के कार्यों से क्यों नहीं जुड़ते ? इस सवाल पर ग्रामीणों का कहना है बंगाल में उन्हें मजदूरी के साथ चावल भी प्राप्त होता है। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत बीपीएल परिवारों को जिले में भी चावल मिलता है। इसपर वे मायूस दिखते हैं। कहते हैं उन्हें बीपीएल कार्ड का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। गांव तक पहुंचने के रास्ते खराब हैं। गांव में संस्थागत प्रसव नहीं होता। गर्भवती महिलाएं आज भी गांव में ही दाई के भरोसे रहती हैं। बीमारी की अवस्था में आज भी लोग गांव में झोला छाप डॉक्टरों पर निर्भर हैं। गांव में बच्चों की संख्या काफी नजर आ रही थी लेकिन स्कूल न होने के कारण वे शिक्षा के बाल-अधिकार से भी वंचित हैं। गांव के परमाणिक पतरस पहाड़िया कहते हैं कि गांव में दो चपाकल हैं, इसमें भी एक खराब है। इन चपाकलों से गर्मी के दिनों में पानी नहीं निकलता और गांववालों को पानी की तलाश में भटकना पड़ता है।

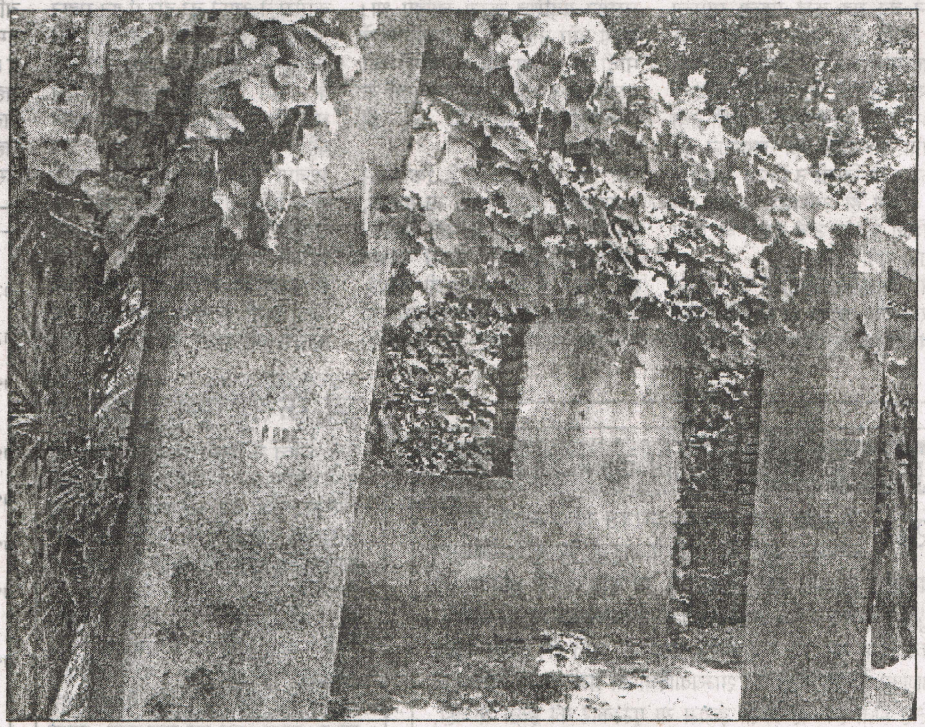

सिंचाई की कमी के कारण खेती प्रभावित : जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर है बबुनी पहाड़ गांव। बबुनी पहाड़ के पास होने के कारण इस गांव का नाम ही बबुनी पहाड़ पड़ गया है और यहां लोगों की जिंदगी भी खुद के लिए पहाड़ बन गई है। गांव में खेती योग्य जमीनें नहीं हैं। पहाड़ का निचला हिस्सा पूरी तरह से बंजर और पठार है। सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके कारण वे चाहकर भी धान की खेती नहीं कर पाते। पठार वाली भूमि पर कहीं-कहीं बाजरा की खेती दिखती है छोटे हिस्से पर लेकिन इसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। गांव में टी.बी की बीमारी के शिकार हैं लोग। इसके साथ आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी घेंघा भी महिलाओं में देखने को मिला। बुसकी पहाड़िन को घेंघा रोग है। यह कहती हैं कि पैसे के आभाव में ईलाज नहीं करवा सकी। गांव के लोग पूर्णतः मजदूरी पर निर्भर हैं। सालोमी पहाड़िन बताती हैं कि टी.बी की बीमारी से गांव के लोगों की मौत हो रही, महिलाएं विधवा हो रही। उसपर विधवाओं को विधवा-पेंशन भी नहीं मिलता। इस गांव तक पहुंचने के लिए उबड़-खाबड़ रास्ते हैं। हिरणपुर के कई पहाड़िया गांव ऐसे हैं जहां तक पहुंचने के लिए कोई रास्ते नहीं है। पैदल ही गांव पहुंचना पड़ता है। ऐसे गांव पूरी तरह से शहर से कटे हुए हैं। न सरकारी अधिकारी कभी यहां तक पहुंच पाते हैं और न ही कोई विकास की योजनाएं यहां तक पहुंच पाती है।

मनरेगा की असफलता पलायन का बड़ा कारण : झारखंड में सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना की षुरूआत एक विजन के साथ की थी। इसके तहत लोगों को अपने ही क्षेत्र में 100 दिन का काम मिलता। गांवों में स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण होता। जिससे पूरे गांव का विकास होता। मसलन कूंआ, तालाब बनने से यह पूरे गांव को सिंचाई की सुविधा, स्वच्छ पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराती । लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। पर्यावरण संरक्षण में लोगों की भागीदारी बढ़ती। महिला, निषक्त, अल्पसंख्यकों को मनरेगा के तहत रोजगार मिल पाता। लेकिन वर्तमान में गांवों की स्थिति देखकर यह स्पष्ट होता है कि मनरेगा अपने उद्देष्यों से भटक गया है। पाकुड़ जिला के मनरेगा लोकपाल रामजीवन लाहिड़ी का कहना है कि पाकुड़ जिले में मनरेगा पूरी तरह से असफल हो चुकी है। जिसके कारण जिले से सबसे ज्यादा पलायन है। सरकार मनरेगा के उद्देष्यों को जमीन पर सही रूप् से उतार पाने में पूरी तरह असफल हो गई है। मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति इसलिए होती है कि वे मनरेगा संबंधित षिकायतों पर तुरंथ कार्रवाई कर सकें। षिकायतों पर जांच कर सके। उत्पन्न त्रुटियों को दूर कर सके लेकिन मनरेगा से संबंधित षिकायतें नहीं आती कार्यालय तक। इसका सबसे बड़ा कारण है कि लोग मनरेगा के कार्यों व उद्देष्यों के प्रति जागरूक नहीं हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि मनरेगा अपने मकसद से ही भटका हुआ है। पाकुड़ जिला में नए पदस्थापित मेसो पदाधिकारी सुनिल कुमार सिंह से आदिम जनजाति पहाड़ियाओं के लिए जिले में चलने वाली योजनाओं की स्थिति पूछने पर वे कहते हैं कि अभी उन्हें पदभार संभाले कुछ ही दिन हुए हैं। इन सबसे परे वे उत्साहित हैं इस बात को लेकर कि गुजरात विकास मॉडल के तहत देषभर में 10 प्रखंडों में से जिले में सबसे कम साक्षरता दर के आधार पर लिट्टिपाड़ा प्रखंड का चयन हुआ है। आदिवासियों व अल्पसंख्यकों के विकास के लिए प्रधानमंत्री की नई योजना वनबंधु कल्याण योजना के तहत लिट्टिपाड़ा प्रखंड का चयन हुआ है। यह बताते हुए वे काफी प्रसन्न नजर आते हैं मानो प्रखंड का सबसे कम साक्षरता दर वाला होना बड़ी उपलब्धि हो।

समाप्त

सीएसडीएस द्वारा प्रदत्त इनक्लूसिव मीडिया यूएनडीपी फेलोशिप के तहत